

अंग्री महांगाई वास्तविक आय को प्रभावित कर रही

बैलेस सीट को सुधारना अच्छा बात है। लेकिन मुनाफे और श्रमिकों को आय के बीच संतुलन भी बने रहना चाहिए। यह नहीं रहा, तो अर्थव्यवस्था में पर्याप्त मांग नहीं बचेगी और कॉर्पोरेट उत्पादों की खरीद नहीं होगी। 'सरकार के कर्ता-धर्ताओं को अहसास होने लगा है कि भारत की 'ग्रोथ स्टोरी' कहीं अटक गई है। वजह आबादी के बहुत बड़े वर्ग की उपभोग क्षमता में गिरावट है। नतीजतन मांग गिर गई है और उसका असर अब कॉर्पोरेट सेक्टर पर भी पड़ रहा है। यह स्थिति बनी रही, तो जीडीपी की तीव्र वृद्धि दर के दावे को कायम रखना कठिन हो जाएगा। वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन की ताजा चिंता का यही संदर्भ है। पिछले हफ्ते एसोचैम के एक आयोजन में उन्होंने कॉर्पोरेट मुनाफे और श्रमिकों की आमदनी के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया। कहा कि कॉर्पोरेट का मुनाफा 15 साल के सबसे ऊँचे स्तर पर है। लेकिन इससे हुई आमदनी के ज्यादातर हिस्से का इस्तेमाल कंपनियों ने ऋण चुकाने में किया है। लेकिन कॉर्पोरेट मुनाफे की तुलना में कर्मचारियों की तनख्या ह नहीं बढ़ी है। नागेश्वरन ने कहा— 'बैलेस सीट को बेहतर करना अच्छी बात है। लेकिन कॉर्पोरेट मुनाफे और श्रमिकों की आय वृद्धि के बीच संतुलन बने रहना चाहिए। यह अनुपात कायम नहीं रहा, तो अर्थव्यवस्था में पर्याप्त मांग नहीं बचेगी और कॉर्पोरेट उत्पादों की खरीद नहीं होगी।' यह वो बात है, जिस पर अनेक विशेषज्ञ पहले से रोशनी डालते रहे हैं। पिछले कुछ समय से कंपनी अधिकारी और मार्केट एजेंसियां भी इस बात को दो-टूक से कहने लगी हैं कि देश में मध्य वर्ग ढह रहा है। इससे संबंधित ताजा रिपोर्ट मार्केट एजेंसी— कैंटार की आई है। शीर्षक गौरतलब है: इंडिया एट ऋक्सरोड्स (चौराहे पर भारत)। कैंटार साउथ एशिया के महानिदेशक सौम्य महंती ने कहा— 'कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था में हुआ सुधार व्यावहारिक रूप में 'के' आकार का रहा है, जिसमें मध्य वर्ग पिस गया है। 2024 में बड़े दायरे में लोग ने महसूस किया कि वे पहले की तुलना में गरीब हो गए हैं। इसका परिणाम उपभोक्ता विश्वास के गतिरुद्ध होने के रूप में सामने आया है।' कैंटार के मुताबिक अगले वर्ष भी मांग मद्दम ही रहेगी, तर्थोंकि ऊँची महंगाई वास्तविक आय को प्रभावित कर रही है। अच्छी बात है कि अब सरकारी अधिकारी भी इसे मान रहे हैं। लेकिन क्या उनके पास कोई समाधान भी है?

मुलायमियत न बरती जाए

हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के कनीना में उन्हाणी गांव के करीब स्कूल बस के पेड़ से टकाराने पर छह बच्चों की मौत वार्कइ दिल कचोटने वाली है। हादसे के वक्त चालक नशे में था। बस में 43 बच्चों समेत एक शिक्षिका भी थी। भिंडंत इन्हीं भीषण थीं कि 34 छात्र घायल हो गए, जिनमें से नौ आईसीयू में हैं। बस चालक, प्रधानाचार्या और स्कूल सचिव को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। चालक तेज गति से वाहन चला रहा था, मोड़ पर संतुलन खोने से बच्चे खिड़कियों से बाहर उछल कर गिर गए। मरने वाले छात्र 13 से 16 साल की उम्र वाले हैं। हादसे के बाद प्रशासन और नेताओं ने रसमादायगी करने में देर नहीं की। इस दुर्घटना में पूर्व मंत्री के परिवार का बच्चा भी मारा गया है। दिल दहलाने वाले इस घटना की उच्चस्तरीय जांच करवाई जाएगी। साथ ही, विद्यालय पर सख्त कार्रवाई की बात भी हो रही है। पुनः यह बात नहीं की जा रही कि छात्रों की जिंदगी को जोखिम में डालने वालों पर नकेल कैसे डाली जाए। देश भर से कहीं—न—कहीं से इस तरह के हादसों की खबरें आती रहती हैं। स्कूलों के लिए विभिन्न नियम बनाए जाते हैं मगर उनको निर्धारित करने और उन्हें सख्ती से लागू करने वालों को जिम्मेदार नहीं बनाया जाता। थोक के भाव में गली—गली स्कूल खोले जा रहे हैं, उन पर दूर—दराज से बच्चों को लाने—ले जाने की परिवहन व्यवस्था करनी होती है जिसके प्रति बेहद लापरवाही बरती जाती है। जब भी इस तरह के हादसे महानगरों के बाहर होते हैं तो उन्हें उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता। शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय समेत संबंधित अधिकारियों को भी अहसास कराया जाना जरूरी है कि उन्होंने घोर लापरवाही बरती है। गैर—जिम्मेदारी सिफर मोटी रकम वसूलने वाले निजी विद्यालय ही करते, बल्कि सरकारी स्कूलों की स्थिति और भी खराब है। अभिभावकों के पास प्रायः न्यूनतम अधिकार होते हैं, उनकी शिकायतों की अनसुनी की जाती है। यदि वे सख्ती से किसी तरह की आलोचना करते हैं तो बच्चे के प्रति अनुचित बर्ताव होने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं, या उन्हें स्कूल से निलंबित करने की धमकियां दी जाती हैं। हादसे के बाद नये—नये नियम लादने से भी कोई सुधार नहीं होने वाला। मारे गए बच्चों के अभिभावकों की क्षतिपूर्ति तो असंभव है,

द रोशंस की रिलीज तारीख से उठ पर्दा, 17 जनवरी से नेटफिलक्स पर दिखेगी तीन पीड़ियों की विरासत

टीवी एक्ट्रेस दीपिका ने थुरू की शूटिंग, जल्द ही साझा करेगी क्या नया कर रही है?

दीपिका ककड़ टीवी सीरियल सुसुराल सिमर का के जरिए दर्शकों के बीच मशहूर हुई थी। इसके अलावा भी उन्होंने कई हिट टीवी सीरियल्स में काम किया। टीवी एक्टर शोएब इब्राहिम से शादी के बाद वह अपनी फैमिली लाइफ में व्यस्त हो गई। उनका एक छोटा बेटा भी है, जिसकी परवरिश में वह अपना पूरा समय देती है। लेकिन टीवी सीरियल में काम ना करने के बावजूद भी वह लाइमलाइट में बनी रहती है। दीपिका टीवी सीरियल में एक्टिव ना होने के बावजूद भी, दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाए हुए हैं। दरअसल, वह अपना एक ब्लॉग चैनल यूट्यूब पर चलाती है। इस चैनल का नाम 'दीपिका' की टिनियां है।

अडानी पर आरोप डीप स्टेट की साजिश का प्रोपेरेड

हरिंशंकर व्यास

भारत पूजावाद का नया इतिहास रच रहा है! भारत मानों गौतम अडानी का गिरवी हो गया है! यदि अडानी ग्रुप का कोई भी भंडा फूटे तो वह दुश्मन के 'डीप स्टेट' की साजिश है! उसकी बात करना, उस पर संसद में बहस चाहना विपक्ष का देशद्रोह है। भारत को अस्थिर बनाना है। सीधे प्रधानमंत्री पर हमला है! सत्ता और सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ साजिश है! दुनिया की नंबर एक महाशक्ति अमेरिका के 'डीप स्टेट' का भारत पर हमला है! इसलिए हम अमेरिका को एकसपोज करेंगे। अमेरिका से लड़ेंगे विपक्ष की बोलती बंद करेंगे। विपक्ष, नेता विपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उस नेहरू-गांधी परिवार को देशद्रोही करार देंगे, जिसने देश को पचास साल चलाया। यह परिवार अमेरिका, उसकी संस्थाओं, उसकी 'डीप स्टेट' का पि है। ये भारत के जगत सेठ गौतम अडानी के खिलाफ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसने अमेरिका और दुनिया के खरबपति पूंजीपतियों को पछाड़ा है वे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व-कृतित्व की उस इकलौती उपलब्धि, 140 करोड़ भारतवासियों की आन-बान-शान के विरोधी हैं, जबकि वह सब सो करोड़ भूखों के फी लंगर की शान है। देश-दुनिया में मोदीजी की आन है, जिससे भारत सोने की चिड़िया बना है। दुनिया में, पूंजीवाद के इतिहास का ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जो अडानी का है। इतिहास में नए पुराने जितने खरबपति-अरबपति हुए हैं उनमें आज तक ऐसा

जनसंख्या विवाद से उठा पर्दा, तीन पीढ़ियों की विरासत को परिभाषित करता है। देखिए दो रोशनी, 17 जनवरी को केवल नेटफिल्म्स पर।

पोस्ट पर फैंस की खुशी थमने का नाम नहीं ले रही थी। एक व्यक्ति ने शूटिंग, जल्द कर रही है? परलगभग 3 मिलियन फॉलोअर हैं। हाल ही में अपने ब्लॉगिंग चैनल पर ही दीपिका ककड़ ने बताया कि वह जल्द ही एक दर्शकों को एक खास प्रोजेक्ट में नजर आएंगी। इसी ब्लॉग में वह शूटिंग वाली जगह पर भी नजर आई। शूटिंग पर उनके बेटा भी साथ में मौजूद था। दीपिका ने कहा कि वह जल्द ही बताएंगी कि किस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रही हैं। दीपिका के यूट्यूब चैनल पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है लेकिन उहें अकसर ट्रोलिंग का शिकार भी होता है। अकसर कुछ सोशल मीडिया युजर्स दीपिका ककड़ और उनके पति शोएब इब्राहिम को उनके रहन-सहन और पहनावों की लेकर टोल कर देते हैं।

एक भा पूंजीपति नहीं हुआ है जिस पर गोलमाल के आरोप लगे और वह राष्ट्र का घोरब बने? उसकी रक्षा के लिए राष्ट्र, सरकार, संसद सब कुरबान हो तथा विपक्ष या विरोधी भ्रष्टाचार का शोर करें तो उससंद में बहस न हो। उलटे विपक्ष को विदेश का पूँ करार दिया जाए। मीडिया खबरें न छाप। और अडानी के लिए सरकार, उसके चेहरे सब वैसी ही जनसंपर्क, लॉबी की भूमिका में हों जैसे कभी धीरूभाई अंबानी के लिए दिल्ली में बालू और टोनी किया करते थे। अंबानी पर भी कई बार बवाल हुए। लेकिन मुझे ध्यान नहीं है कि इंदिरा गांधी, प्रणब मुखर्जी या किसी भी सरकार ने धीरूभाई अंबानी को भारत की आन-बान-शान करार दे कर उनके खिलाफ अमेरिका की 'डीप स्टेट' या सीआईए की साजिश बताई हो। या संसद में बहस नहीं होने दी हो। या वाणिज्य, वित्त आदि की किसी भी भूमिका में प्रणब मुखर्जी ने रिलायंस का बचाव किया हो। इसलिए समकालीन इतिहास में प्रधानमंत्री ने देश के जो कर्म किया है वह न केवल पूंजीवाद और आजाद भारत के इतिहास की अनहोनी है, बल्कि यह सवाल भी बनाते हुए है कि अडानी पर हळ्ड किसे है कि गली-गली में शोर अडानी का है और घबराई हुई सरकार है। इतना ही नहीं भाजपा और उसके प्रवक्ता सब अडानी के कारतूस बने हुए हैं। यदि अमेरिकी

गरावट पर

संघ प्रमुख ने जिस आशंका को प्रकट किया है, उससे सार्वजनिक जीवन में सक्रिय जनप्रतिनिधियों का एक समूह परिचित तो है, लेकिन अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों के कारण उसे जनविमर्श का हिस्सा बनाने से न सिर्फ बचता है, बल्कि उसे नया रंग देने का प्रयास भी करता है।

आरोप-प्रत्यारोपों को दरकिनार कर क्या हमें हकीकत को नहीं देखना चाहिए? क्या यह सच नहीं कि भारतीय उपमहाद्वीप (भारत सहित) में हिंदुओं की जनसंख्या, मुस्लिमों के अनुपात में लगातार घट रही है? क्या मजहब का भारत की एकता-अखंडता और इस राष्ट्र के शाश्वत मूल्यों-बहुलतावाद, लोकतंत्र और सेकुलरवाद के साथ सीधा संबंध है या नहीं? देश में जहां-जहां आज हिंदू अल्पसंख्यक है, उनमें से अधिकतर क्षेत्र क्या अलगाववाद से ग्रस्त नहीं? संघ प्रमुख के विचार पर त्वरित कोई रय बनाने से फहले क्या इन सवालों के जवाब ईमानदारी से खोजने चाहिए।

क्या यह सत्य नहीं कि ब्रिटिशकालीन भारत, जनसंख्यकीय में आए परिवर्तन के कारण ही विभाजित हुआ था? इस त्रासदी में जिन दो मुल्कों- पाकिस्तान और बांग्लादेश का जन्म हुआ, वह घोषित रूप से इस्लामी है। अपने वैचारिक

17 जनवरी की विरासत

लेखा, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ! कांटेंटाउन शुरू हो चुका है, जबकि दूसरे ने लिखा, ह्याद रोशन्स़ह की विरासत देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। एक और कमेंट में लिखा गया, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के महान लोगों पर प्रेरणादायक डॉक्यूमेंट्री देखने का इंतजार है। 17 जनवरी - तारीख सेव कर ली। कई अन्य फैंस ने रेड हार्ट और फायर इमोजी के साथ अपनी भावनाएं व्यक्त की।

द रोशंस का निर्देशन शशी रंजन ने किया है। सूत्रों के मुताबिक इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में बॉलीवुड के कई सेतारों के इंटरव्यू भी होंगे, जिन्होंने रोशन परिवार के साथ काम किया है। राकेश रोशन ने इस साल की शुरुआत में शाहरुख खान का द रोशंस में योगदान के लिए धन्यवाद किया था।

वनवास का नया गाना छबीली के नैना जारी, नाना पाटेकर ने खुद गाया

हिंदी सिनेमा के जाने-माने निर्देशक अनिल शर्मा पिछले काफी समय से अपनी आगामी फिल्म वनवास को लेकर सुरियों बटोर रहे हैं। इस फिल्म में उनके बेटे और अभिनेता उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर भी इस फिल्म अहम हिस्सा हैं। वनवास को आज 20 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। रिलीज से एक दिन पहले अब निर्माताओं ने फिल्म का नया गाना छबीली के नैना जारी कर दिया है। खास बात यह है कि वनवास के नए गाने छबीली के नैना को पाटेकर ने खुद गाया है।

अधिष्ठान के अनुरूप इन दोनों ही देशों में हिंदू, बौद्ध और सिख आदि अल्पसंख्यकों के लिए न तो कोई स्थान है और न ही उनके मानविंतु (मंदिर-गुरुद्वारा सहित) सुरक्षित। विडंबना है कि सिंधु नदी, जिसके तट पर हजारों वर्ष पूर्व ऋषि परंपरा से वेदों की रचना हुई- उस क्षेत्र में आज उनका नाम लेने का कोई नहीं बचा है। भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वाधिक 'असुरक्षित' कौन है? विश्व के इस भूखंड में कुल मिलाकर 180 करोड़ लोग बसते हैं, जिसमें भारत 140 करोड़, पाकिस्तान 23 करोड़ और बांग्लादेश की आबादी 17 करोड़ है। 180 करोड़ में 112 करोड़ हिंदू हैं, जबकि मुस्लिम 62 करोड़ से अधिक मुस्लिम। विभाजन से पूर्व, इस भू-भाग की कुल आबादी में हिंदू-सिख-बौद्ध-जैन अनुयायियों का अनुपात 75 प्रतिशत, तो मुस्लिम अनुपात 24 प्रतिशत था। स्वाधीनता से लेकर आज तीनों देशों में हिंदू-सिख-बौद्ध-जैन घटकर 62 प्रतिशत रह गए हैं, जबकि मुस्लिम बढ़कर 34 प्रतिशत हो गए। आज हिंदुओं-सिखों-बौद्ध-जैन की जो वास्तविक संख्या 135 करोड़ या उससे अधिक होनी चाहिए थी, वह घटकर 112 करोड़ रह गई है। यक्ष प्रश्न है कि इस भूखंड से पिछले सात दशकों में 23 करोड़ हिंदू-सिख-बौद्ध-जैन कहाँ गायब हो गए? बात यदि खंडित भारत की करें, तो अरुणाचल प्रदेश में 2001 से 2011 के बीच हिंदुओं की जनसंख्या 5.56 लakh तक घट गई है। वर्ष 1971 में इस प्रदेश की कुल जनसंख्या में ईसाई एक प्रतिशत भी नहीं थे, लेकिन वर्ष 2011 में वे 30 लakh हो गए। इस दौरान बौद्ध अनुयायियों की संख्या भी घट गई है। असम में 2001 की जनगणनीय तुलना में हिंदू आबादी 2011 में लगभग तीन प्रतिशत घटी है। इस दौरान असम में हिंदू वृद्धि दर लगभग 11 लakh, तो मुस्लिम आबादी 29 लakh रही। प.बंगाल में भी हिंदुओं की वृद्धि दर तेजी से घट रही है। केरल में हिंदू जनसंख्या गत 100 वर्षों में 14 प्रतिशत घट चुकी है ख्वतंत्रता से पहले नागालैंड और मिजोरम- दोनों आदिवासी बहुल क्षेत्र थे। दिलचस्प तथ्य है कि वर्ष 1941 में नागालैंड की कुल आबादी में जहां ईसाई लगभग शून्य थे, तो मिजोरम में ईसाई आबादी आधा प्रतिशत भी नहीं थी। परंतु वह एकाएक 1951 में बढ़कर त्रिमाशः 46 और 90 प्रतिशत हो गए। 2011 की जनगणना के अनुसार, दोनों राज्यों की कुल जनसंख्या में ईसाई त्रिमाशः 88 और 87 प्रतिशत है। मेघालय की भी यही स्थिति है। इसी जनसांख्यिकीय स्थिति के कारण इन राज्यों में चर्चा का अत्याधिक प्रभाव है।

अडानी पर आरोप और सोध अमेरिका को 'डीप स्टेट' की साजिश का प्रोपोर्टेंडा! जबकि हाल में अमेरिकी अदालत ने खालिस्तानी पत्रू की हत्या की साजिश में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, पूर्व रॉ चीफ, रॉ एजेंट व एक कारोबारी को समन जारी किया मगर तब तो सरकार और भाजपा ने एक शब्द इनके बचाव में नहीं बोला तब अमेरिकी 'डीप साजिश' का हल्ला नहीं था। लेकिन अडानी की ऐसी चिंता जो संसद का पूरा सत्र इसलिए कुरबान क्योंकि गाहुल गांधी ने अडानी पर लगे आरोपों पर बहस चाही! अमेरिकी अदालत से अडानी ग्रुप को समन है तो भारत के सुरक्षा प्रमुख अजित डोवाल पर भी अमेरिकी अदालत की कारवाई है। एक का कारोबारी-सिविल मामला है तो दूसरा हत्या की साजिश का फौजदारी मुकदमा। सोचें, भारत राष्ट्र-राज्य की आन-बान-शान के लिए कारोबारी-सिविल-भ्रष्टाचार का आरोप अधिक चिंता वाला होना चाहिए या फौजदारी का? प्रधानमंत्री मोदी, सत्तारूढ़ पार्टी को अजित डोवाल एंड पार्टी की रक्षा में संसद में या बाहर यह हल्ला क्या नहीं करना चाहिए था कि अमेरिका की 'डीप स्टेट' भारत के खुफिया प्रमुखों को कटघरे में खेड़ा कर भारत को अस्थिर कर रही है? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत अडानी की बदनाम गौरव गाथा पर कुरबान है न कि भारत की सुरक्षा के रणबांकुरों (डोवाल एंड पार्टी) का अहसानमंद! इस अंतर से क्या साबित होता है? तभी सोचें, प्रधानमंत्री मोदी के लिए उपयोगी कौन अधिक रहा है? अडानी या डोवाल?

बढ़ता डिजिटल सेवा नियात

अशाक ५

आधारित के अनुरूप हिन्दू दाना ही दशा में हिंदू बौद्ध और सिख आदि अल्पसंख्यकों के लिए न तो कोई स्थान है और न ही उनके मानविंदु (मंदिर-गुरुद्वारा सहित) सुरक्षित। विडब्बना है कि सिंधु नदी, जिसके तट पर हजारों वर्ष पूर्व ऋषि परंपरा से वेदों की स्त्राणा हुई-उस क्षेत्र में आज उनका नाम लेने का कोई नहीं बचा है। भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वाधिक 'असुरक्षित' कौन है? विश्व के इस भूखंड में कुल मिलाकर 180 करोड़ लोग बसते हैं, जिसमें भारत 140 करोड़, पाकिस्तान 23 करोड़ और बांगलादेश की आबादी 17 करोड़ है। 180 करोड़ में 112 करोड़ हिंदू हैं, जबकि मुस्लिम 62 करोड़ से अधिक मुस्लिम। विभाजन से पूर्व, इस भू-भाग की कुल आबादी में हिंदू-सिख-बौद्ध-जैन अनुयायियों का अनुपात 75 प्रतिशत, तो मुस्लिम अनुपात 24 प्रतिशत था। स्वाधीनता से लेकर आज तीनों देशों में हिंदू-सिख-बौद्ध-जैन घटकर 62 प्रतिशत रह गए हैं, जबकि मुस्लिम बढ़कर 34 प्रतिशत हो गए। आज हिंदुओं-सिखों-बौद्ध-जैन की जो वास्तविक संख्या 135 करोड़ या उससे अधिक होनी चाहिए थी, वह घटकर 112 करोड़ रह गई है। यक्ष प्रश्न है कि इस भूखंड से पिछले सात दशकों में 23 करोड़ हिंदू-सिख-बौद्ध-जैन कहां गये रहे? बात यदि खाड़त भारत का करें, तो अरुणाचल प्रदेश में 2001 से 2011 के बीच हिंदुओं की जनसंख्या 5.56 लakh तक घट गई है। वर्ष 1971 में इस प्रदेश की कुल जनसंख्या में ईसाई एक प्रतिशत भी नहीं थे, लेकिन वर्ष 2011 में वे 30 लakh हो गए। इस क्षेत्र में आज अनुयायियों की संख्या भी घट गई है। असम में 2001 की जनगणनीय तुलना में हिंदू आबादी 2011 में लगभग तीन प्रतिशत घटी है। इस दौरान असम में हिंदू वृद्धि दर लगभग 11%, तो मुस्लिम आबादी 29% रही। प.बंगल में भी हिंदुओं की वृद्धि दर तेजी से घट रही है। केरल में हिंदू जनसंख्या गत 100 वर्षों में 14 प्रतिशत घट चुकी है। स्वतंत्रता से पहले नागालैंड और मिजोरम- दोनों आदिवासी बहुल क्षेत्र थे। दिलचस्प तथ्य है कि वर्ष 1941 में नागालैंड की कुल आबादी में जहां ईसाई लगभग शून्य थे, तो मिजोरम में ईसाई आबादी आधा प्रतिशत भी नहीं थी। परंतु वह एकाएक 1951 में बढ़कर त्रिमाशः 46 और 90 प्रतिशत हो गए। 2011 की जनगणना के अनुसार, दोनों राज्यों की कुल जनसंख्या में ईसाई त्रिमाशः 88 और 87 प्रतिशत है। मेघालय की भी यही स्थिति है। इसी जनसंख्यकीय स्थिति के कारण इन राज्यों में चर्च का अल्पाधिक प्रभाव है।

इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना तकनीक से सबोधन वस्तुओं के बढ़ते नियात के साथ-साथ भारत डिजिटल माध्यम से मुहैया करायी गयीं सेवाओं के नियात में भी वैश्विक बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी अंकड़ों के अनुसार 2023 में भारत ने 257 अरब डॉलर मूल्य के ऐसी सेवाओं का नियात किया है, जो 2022 की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है। इस क्षेत्र में भारत जर्मनी और चीन को पीछे छोड़ते हुए चौथे स्थान पर आ गया है। अब भारत से आगे केवल अमेरिका, ब्रिटेन और आयरलैंड हैं। डिजिटल माध्यम से सेवा मुहैया कराने का अर्थ यह है कि कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल कर शिक्षा, गेमिंग, मनोरंजन, अर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि के लिए दक्ष ऑपरेटर, कुशल प्रोग्रामर और कोडिंग विशेषज्ञ अपनी सेवाएं देते हैं। वैश्विक सेवा व्यापार में डिजिटल माध्यम से मुहैया करायी जाने वाले सेवाओं का हिस्सा अब 20 फीसदी से भी ज्यादा हो गया है। यह अंकड़ा 2005 में 14 प्रतिशत था। वस्तुओं के नियात में कई कारणों- भू-राजनीतिक तनाव, हिंसक संघर्ष, आपूर्ति शृंखला में अवरोध, मुद्रास्फीति में वृद्धि, मांग में कमी आदि- से बीते वर्षों में उतार-चढ़ाव होता रहा है। हालांकि इस वर्ष बेहतरीन की उम्मीद जतायी जा रही है, लेकिन आशंकाएं भी बनी हुई हैं।

इस रुझान के उलट कोरोना महामारी के दौर से पहले के तुलना में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल सेवाओं का नियात अभी 50 प्रतिशत से अधिक के स्तर पर है। इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा भी बहुत है क्योंकि कई देश सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग, कोडिंग आदि डिजिटल क्षमताओं को बढ़ाने में जुटे हैं। अनेक देश ऐसी सेवाओं के आयात करने के बजाय अपने देश में इन्हें विकसित कर रहे हैं, भले ही उनकी गुणवत्ता कमतर हो। फिर इन सेवाओं से डाटा सुरक्षा और संग्रहण के मुद्दे भी जुड़े होते हैं। ऐसी स्थिति में भारत से डिजिटल सेवा नियात में उल्लेखनीय वृद्धि से यह इंगित होता है कि इन सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता उत्कृष्ट है तथा सुरक्षा को लेकर भी भारतीय सेवा प्रदाताओं पर भरोसा बढ़ा है। बीते वित्त वर्ष में अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 के बीच भारत से वस्तुओं और सेवाओं का कुल नियात 709 अरब डॉलर से अधिक रहा है तथा इस अवधि में हमारा कुल आयत 782 अरब डॉलर से ज्यादा हुआ है। हाल के वर्षों में भारत सरकार ने आर्थिक सुधारों, नीतिगत पहलों तथा प्रोत्साहन कार्यक्रमों के माध्यम से गुणवत्ता पूर्ण उत्पादन तथा नियात बढ़ाने को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। घरेलू बाजार में भी देशी उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

अश्विन के संन्यास पर जड़ेजा ने कहा: आरिकरी क्षण में पता चला

मेलबर्न, भारत के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने खुलासा किया कि कैसे गविंद्रन अश्विन के अचानक संन्यास ने प्रशंसकों और टीम के साथियों को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें सार्वजनिक घोषणा से कुछ क्षण पहले ही इसके बारे में पता चला। जडेजा ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) में संवाददाताओं से कहा, मुझे आखिरी क्षण में संन्यास के बारे में पता चला। प्रेस कॉम्प्लेक्स से से पांच मिनट पहले। यह चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, हमने पूरा दिन साथ बिताया, और उसने मुझे संकेत भी नहीं दिया। हम सभी जानते हैं कि अश्विन का दिमाग कैसे काम करता है (हँसते हुए)। अश्विन और जडेजा एक दशक से अधिक समय में टेस्ट क्रिकेट में शपथ के गेंदबाजी



कैएल राहुल के साथ कौन करेगा ओपनिंग? खतरनाक होने वाली है दिल्ली कैपिटल्स की जोड़ी

नईदिल्ली, आईपीएल 2025 मेंगा
अंक्षान में केएल राहुल को दिल्ली
कैपिटल्स ने 14 करोड़ रुपये में खरीदकर
अपने साथ जोड़ लिया। हालांकि, अब तक
फेंचाइजी ने इस बात की आधिकारिक
घोषणा नहीं की है की केएल ही टीम के
कपान बनेंगे। मगर, ये बात तो तय है की
केएल अपकर्मिंग सीजन में दिल्ली के लिए
क्रिकेट करते नजर आएंगे। लेकिन,
सवाल ये है की केएल के साथ ओपनिंग
करने कौन आएगा? आइए आपको केएल
के ओपनिंग पार्टनर के बारे में बताते हैं।
भारतीय स्टार ट्रिकेटर केएल राहुल
आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स की

पारी की शुरुआत कौन करेगा? यदि आप भी इसका जवाब तलाश रहे हैं, तो आपको बता दें दिल्ली ने आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हुए जेक फेसर मैकगर्क को अपने साथ वापस जोड़ा। इस खिलाड़ी का केएल के साथ ओपन करना तय माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने पिछले सीजन भी तूफानी शुरुआत दिलाई थी। जेक फेजर-मैकगर्क ने पिछले सीजन ही दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा रहते हुए अपना आईपीएल डेब्यू किया। फैंचाइजी ने कुल 9 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 36.67 के औसत और 234.04 की खतरनाक स्ट्राइक रेट से 330 रन बनाए हैं।

